1	2	3	4	5	6
26.	A&N Islands				17.00
27.	Delhi				16.00
28.	BAIF				58.00
29.	Lakshedweep				

Statement III

Targets fixed for Power Generation Programme during the year 1994-95

Sl. No.	Programme	Units	Targets (1994-95)
1.	Wind Power	MW	10
2.	Small Hydro Power	MW	25
3.	Biomass based Co-generation	MW	30
4.	Biomass Combustion	MW	10
5.	Biomass Gasifer based power	MW	0.5
6.	Biomass Stand-alone Gasifiers	MW	5
7.	Grid connected SPV Power	MW	0.2
8.	SPV Power Plants (Small)	KW	100
9.	Wind battery chargers	KW	30

जल-विद्युत उत्पादन

2786. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेषत: देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फैली लगभग 3,200 किलोमीटर लम्बी हिमालय पर्वतमाला में विद्यमान असंख्य जल प्रपातों में 10,000 मेगावाट जल-विद्युत उत्पादन की क्षमता है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षमता में से इस समय केवल 114 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो दिसंबर 1994 के अंत तक इस स्रोत से विद्युत का कितना उत्पादन किया गया था;

(ङ) क्या सरकार ने इस संभावित उपलब्ध क्षमता के उपयोग हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूप-रेखा क्या है और यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) और (ख) मोटे अनुमानों के अनुसार देश में लगभग 10,000 मेगा० की लघुपन बिजली परियोजनाओं की संभाव्यता है। हिमालयी क्षेत्रों में संभाव्यता का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए अभी विस्तृत अध्ययन किए जाने हैं।

(ग) और (घ) इस समय 3 मेगा० क्षमता तक की लघुपन बिजली परियोजनाओं की क्षमता 114 मेगा० है;

(ङ) और (च) देश के हिमालयी और उप-हिमालयी क्षेत्रों में लघु पन बिजली संसाधनों के इष्टतम विकास और उपयोग के कार्य में सरकार की सहायता के लिए बनाई गई यू एन डी पी/जीईएफ तकनीकी परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को 42 महीनों में कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डालर की यूएनडीपी सहायता और

22.48 करोड़ रुपए के भारतीय प्रतिरूप निधियन की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य हिमालयी और उप-हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना है।

Solar Power in UP

2787, SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the steps taken to encourage '"Solar Power" in Uttar Pradesh";

(b) whether any incentive programmes have been drawn to popularise the "Solar Energy System" there; and

(c) if not, whether Government would consider the starting of scheme in other States also?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Government is implementing socially oriented and market oriented schemes to encourage the use of stand alone (non grid-interactive) solar photovoltaic (SPV) including devices/systems for solar power generation in the country, including the State of Uttar Pradesh. The SPV systems insalled in Uttar Pradesh as on 28.2.95 include 470 street lights, 18562 domestic lighting systems, 6825 solar lanterns, 50 television systems, 70 water pumping systems and 32 small village level non grid-interactive power plants of an aggregate SPV capacity of 150KWP. In addition, 2 Nos. of SPV power plants each of capacity 100 KW with partly grid-interactive components, have been set up •in the village Sarai Sadi district Mau and village Kalayanpur, district Aligarh in Uttar Pradesh.

(b) and *{c).* The Government is popularising solar power, through the promotion of solar photovoltaic systems, which are being manufactured in the country. For this purpose various incentives arc being provided. These include a central subsidy of 50% of the ex-works costs of solar photovoltaic systems for lighting and village level small power plants to special category States Uts, Islands, desert areas, hilly regions and certain specific categories of beneficiaries all over the country under the Socially Oriented Scheme. The Subsidy for solar lanterns is fixed at Rs. 2,000/- each. A package of subsidy and soft loans is also being made available for the purchase of SPV Water pumping Systems.

Further, soft loans are being made available to beneficiaries for purchase of Solar Photovoltaic devices/systems through the Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) Ltd. under the Market Oriented Scheme. A World Bank assisted project of US $ 55 million value for SPV market development in the country is also being implemented through IREDA.

In addition to the above incentives for users, fiscal and financial incentives such as concessional custom duties on solar cells, photovoltaic modules and systems, concessional excise duty, 100% depreciation and soft loan facilities are also being made available to manufacturers of solar photovoltaic devices and systems.

सोलर कुकर के लिए राज सहायता

2788. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1994 से पूर्व राज्यों को प्रति सोलर कुकर कितनी धनराशि की राज सहायता प्रदान की जा रही थी और उसके पश्चात उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) प्रत्येक सोलर कुकर की कीमत कितनी निर्धारित की गई है; और

(ग) देश में सोलर कुकर को और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) सौर कुकर की खरीद पर उपयोगकर्ताओं को केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता के भुगतान के लिए राज्यों को 31 मार्च, 1994 तक 150/-